Roll No	Question Booklet No.
O.M.R. Serial No.	प्रश्नपुस्तिका सिरीज Question Booklet Series

पश्चपस्तिका क्रमांक

B.A.LL.B (Fourth Semester) Examination, January-2022 B.A.LL.B404 (PAPER-IV) ADMINISTRATIVE LAW

Time: 1:30 Hours Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही– सही भरें, अन्यथा मुल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 - इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमे से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने है। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET)में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वांइट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।

प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।

- सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने 4. हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
- ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
- निगेटिव मार्किंग नहीं है। 7.

महत्वपूर्ण : -प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जॉच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभॉति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

- 1. A given promise, which goes against the public interst and is against public policy is-
 - (A) Enforceable by principle of promissory estoppel
 - (B) Not enforceable by principle of promissory estoppel
 - (C) Partially enforceable
 - (D) Partially non enforceable
- 2. The Principle of Promissory estoppel-
 - (A) Is based on principle of equity
 - (B) Is much wider in scope and application as compared to estoppel defined under section 115 of Indian Evidence Act
 - (C) States that a promise made must be ful filled and honoured and can not be denied later to the detriment of other person
 - (D) All the above are true
- 3. Now all the public corporations are considered to be-
 - (A) An instrumentality of the state and hence state as defined in Article 12 of the constitution
 - (B) Are not state under Article 12 of the constitution
 - (C) Both state under Article 12 of the constitution and a legal person
 - (D) (A) and (C) both are true
- 4. Which among the following is not a Public corporation-
 - (A) Reserve Bank of India
 - (B) Damodar Valley corporation
 - (C) Tata Services consultancy
 - (D) Road Transport corporation

- 1. एक दिया गया वचन जो लोक हित तथा लोक नीति के विरूद्ध हो, तब वह—
 - (A) वचनीय विबन्ध सिद्धान्त के अनुसार प्रवर्तनीय होगा
 - (B) वचनीय विबन्ध सिद्धान्त पर अप्रवर्तनीय होगा
 - (C) आंशिक प्रवर्तनीय होगा
 - (D) आंशिक अप्रवर्तनीय होगा
- 2. 'वचनीय विबन्ध' का सिद्धान्त-
 - (A) साम्या पर आधारित है
 - (B) सीमा तथा प्रयोज्यता में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित 'विबन्ध' से अधिक व्यापक है
 - (C) कहता है दिये गये वचन को पूरा करना, तथा सम्मान देना चाहिए और बाद में उससे मुकरा नही जा सकता दूसरे व्यक्ति का हानि पहुँचाने के दृष्टि से
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
- 3. अब सभी लोक निगम माने जाते है-
 - (A) राज्य उपक्रम अतः संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'राज्य' है
 - (B) संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य नहीं है
 - (C) संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य तथा विधिक व्यक्ति भी
 - (D) (A) और (C) दोनों सही है
- 4. निम्न में से कौन लोक निगम नहीं है-
 - (A) भारतीय रिजर्व बैंक
 - (B) दामोदर घाटी कारपोरेशन
 - (C) टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज
 - (D) सड़क परिवहन कारपोरेशन

- 5. A public corporation is-
 - (A) Created by statute and as such has legal personality
 - (B) It can sue and be sued and has contractual tortious and criminal liability
 - (C) Is autonomous in character
 - (D) All the above are true
- 6. Choose the <u>best option -</u>
 A Public Corporationis a hybrid entity because it has-
 - (A) Features of a government department
 - (B) Features of a commercial company
 - (C) Having some features of a government department and some features of a business company
 - (D) Is a constitutional body
- 7. The most frequently issued writs by Supreme Court and High Courts to correct. Administrative mal functioning negligence-
 - (A) Mandamus and prohibition
 - (B) Quowarranto and prohibition
 - (C) Mandamus and Quowarranto
 - (D) None of the above

- 5. एक लोक निगम-
 - (A) का निर्माण अधिनियम द्वारा होता है अतः इसका अपना विधिक व्यक्तित्व होता है
 - (B) यह वाद संस्थित कर सकता है तथा इसके विरूद्ध भी वाद संस्थित हो सकता है अतः इसके संविदात्मक, अपकृत्य संबंधी तथा आपराधिक दायित्व होते है
 - (C) स्वायतशासी प्रकृति की होती है
 - (D) उपरोक्त सभी सत्य है
- 6. <u>सर्वश्रेष्ठ विकलप चुने</u>— एक लोग निगम एक मिश्रित निकाय है क्योंकि—
 - (A) इसमें सरकारी विभाग के लक्षण होते है
 - (B) वाणिज्यिक कम्पनी के लक्षण होते है
 - (C) थोड़े लक्षण सरकारी विभाग तथा थोड़े लक्षण वाणिज्यिक कंपनी के होते है
 - (D) एक संवैधानिक निकाय है
- 7. प्रशासनिक कार्यो में लापरवाही तथा दुरूपयोग को सही करने के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा बहुधा जारी की जाने वाली रिट होती है—
 - (A) परमादेश तथा प्रतिषेध
 - (B) अधिकारपृच्छा तथा प्रतिषेध
 - (C) परमादेश तथा अधिकारपृच्छा
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 8. In exercise of judicial Review power by the Supreme Courtand High Court with regard to Administrative actions they use their-
 - (A) Jurisdiction under Artcle 32
 - (B) Jurisdiction under Article 226
 - (C) Jurisdiction under Article 32 by Supreme Court and Jurisdiction under Article 226 by High Courts
 - (D) None of the above
- 9. The office of Prime minister now-
 - (A) Comes under the purview of lokpal enquiry
 - (B) Does not comes under the lokpal enquiry
 - (C) Office of Prime minister does not but other Central Minister come under Lokpals enquiry
 - (D) None of the above
- 10. The institution of lokpal and lokayuktas has in India has a-
 - (A) Constitutional status
 - (B) Only a statutory status
 - (C) Both constitutional and statutory status
 - (D) Neither constitutional nor statutory status

- 8. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयो द्वारा प्रशासनिक कार्यो का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते वक्त व प्रयोग करते है—
 - (A) अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का
 - (B) अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का
 - (C) उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयो द्वारा अनुच्छेद 226 की अधिकारिता का
 - (D) उपरोक्त मे से कोई नहीं
- 9. प्रधानमंत्री का पद अब-
 - (A) लोकपाल की जाँच के दायरे मे है
 - (B) लोकपाल के जाँच दायरे से बाहर है
 - (C) प्रधानमंत्री को छोडकर अन्य सभी केन्द्रीय मंत्री लोकपाल जाँच के दायरे में होंगे
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 10. भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्तो की संस्था को प्राप्त है—
 - (A) संवैधानिक हैसियत
 - (B) सांविधिक हैसियत
 - (C) दोनों संवैधानिक तथा सांविधिक हैसियत
 - (D) न ही संवैधानिक हैसियत और न ही सांविधिक हैसियत

- 11. The Lokpal and Lokayuktas Bill was passed by Indian Parliament45 years after its introduction in Loksabha on the date-
 - (A) 18th December 2013 with presidential assent on 1st January 2014
 - (B) 10th December 2013 with president assent on the same date
 - (C) 1st January 2013 and president assent on the same date
 - (D) None the above
- 12. The function of Ombudsman is to-
 - (A) Conduct enquivry with regard to public grievances against abuse of administrative discretion, corruption related practices, misconduct and negligience of duties by public official and public servants and give recommendations.
 - (B) Raise matters of public importance in Media
 - (C) To institute writ petition against corrupt officials and peoples representatives
 - (D) All the above

- 11. लोकपाल तथा लोकायुक्त विधियेक लोकसभा में प्रथम बार प्रस्तुत होने के 45 वर्ष पश्चात संसद द्वारा पारित किया गया—
 - (A) 18 दिसम्बर 2013 को, जिसे राष्ट्रपति को सम्मति, 1 जनवरी 2014 को प्राप्त हुई
 - (B) 10 दिसम्बर 2013 को तथा उसी दिन राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई
 - (C) 1 जनवरी 2013 को तथा उसी दिन राष्ट्रपति सम्मति प्राप्त हुई
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 12. ओमबुड्समैन का कार्य है-
 - (A) लोक शिकायतों पर जो कि प्रशासनिक अधिकारयों तथा लोक सेवको द्वारा विवेकीय शक्तियों के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार संबंधित कार्यप्रणाली, कदाचार तथा उनके द्वारा कर्त्तव्यों में घोर लापरवाही इत्यादि मामलों की जाँच करना तथा अपनी अनुशंसा समाधान हेत् करना
 - (B) मीडिया में जन सामान्य के महत्वपूर्ण मामले उठाना
 - (C) भ्रष्ट अधिकारियो तथा जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल करना
 - (D) उपरोक्त सभी

- 13. The institution of ombudsman originated in 1809 at-
 - (A) Sweden
 - (B) France
 - (C) Germany
 - (D) Switzerland
- 14. Public interest litigation may be filed by apublic spirited citizens for-
 - (A) Protecting the rights and interest of economically poor uneducated and depriued section of society in case of violation of their fundamental rights cause
 - (B) Public cause and public interest matters of great importance
 - (C) Public cause and not for publicity or political gains
 - (D) All the above are correct
- 15. Rule of Locusstendei is not applicable to-
 - (A) Private litigations
 - (B) Public interest litigation
 - (C) Arbitration proceedings
 - (D) To both (A) and (C)

- 13. 'ओमवुड्समैन' संस्था का प्रादुर्भाव 1809 मे हुआ था—
 - (A) स्वीडन में
 - (B) फ्राँस में
 - (C) जर्मनी में
 - (D) स्विटज्रलैंड में
- 14. लोक हित वाद किसी ऐसे नागरिक द्वारा जो कि लोक भावना से प्रेरित हो दाखिल किया जा सकता है—
 - (A) आर्थिक रूप से विपन्न, अशिक्षित तथा समाज के वँचित वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितो के संरक्षण हेतु
 - (B) लोक निमित्त तथा जन हित संबंधित महत्वपूर्ण मामलो के लिए
 - (C) लोक निमित्त हेतु न कि व्यक्तिगत वाह—वाही तथा राजनीतिक लाभ हेतु
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
- 15. वाद दाखिल करने में हित संबंधी औपचारिकता का नियम लागू नहीं होता है—
 - (A) प्राईवेट विवादो पर
 - (B) लोक हित वाद पर
 - (C) मध्यस्थम कार्यवाहियो पर
 - (D) दोनो (A) और(C)पर

- 16. A subordinate having no jurisdiction takes a case for hearing and passes preliminary order on some issues in favour of the plaintify and reserves other issues for next hearing. The defendant can getremedy by which of the writ/writs-
 - (A) By writs of certiorari and prohibition respectively
 - (B) Writs of prohibition and certiorari respectively
 - (C) Only from certiorari
 - (D) Only from prohibition
- 17. A person ursurping a public office without having right authority to do so then proper writ against him would be-
 - (A) Quo-warranto
 - (B) Certiorari
 - (C) Both Quowarranto and certiorari
 - (D) Prohibition
- 18. When any public authority on demand refuses to carry out his public duty, then against him which writ can be filed against him-
 - (A) Mandamus
 - (B) Quo-warranto
 - (C) Prohibition
 - (D) Certiorari
- 19. The writ based on the principle of 'Prevention is better than cure' is-
 - (A) Prohibition
 - (B) Mandamus
 - (C) Certiorari
 - (D) None of the above

- एक अधीनस्थ न्यायालय बिना अधिकारिता के वाद की सुनवाई करता है। सुनवाई के दौरान कुछ मुद्दों पर वादी के पक्ष में प्रारंभिक आदेश पारित कर देता है तो शेष वाद बिन्दुओं को अगली सुनवाई हेतु टाल देता है प्रतिवादी कौन सी रिटो से उपचार प्राप्त कर सकेगा—
 - (A) क्रमशः उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध से
 - (B) क्रमशः प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण से
 - (C) केवल उत्प्रेषण से

16.

- (D) केवल प्रतिषेध से
- 17. एक व्यक्ति जो बिना अधिकार अथवा प्राधिकार के एक लोक पद पर काबिज हो जाता है तो उसके विरूद्ध कौन सी रिट उपयुक्त रिट दाखिल होगी—
 - (A) अधिकार पृच्छा
 - (B) उत्प्रेषण
 - (C) अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण दोनों
 - (D) प्रतिषेध
- 18. जब कोई लोक प्राधिकारी माँग करने पर भी अपने लोक कर्त्तव्य का पालन न करे, तो उसके विरूद्ध कौन सी रिट दाखिल की जा सकती है—
 - (A) परमादेश
 - (B) अधिकारपृच्छा
 - (C) प्रतिषेध
 - (D) उत्प्रेषण
- 19. कौन सी रिट "उपचार से सावधानी भली" सिद्धान्त पर आधारित है-
 - (A) प्रतिषेध
 - (B) परमादेश
 - (C) उत्प्रेषण
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 20. Which among the following writs is curative in nature-
 - (A) Writ of Mandamus
 - (B) Writ of Quo-warranto
 - (C) Writ of Habeas Corpus
 - (D) Writ of Certiorari
- 21. The writ jurisdiction of supreme and High Courts of the state is contained in which of the following Articles of the constitution-
 - (A) Articls 32 and 217
 - (B) Articls 32 and 266
 - (C) Articls 32 and 226
 - (D) Articls 136 and 226
- 22. A writ petition can be filed in which of the following Courts-
 - (A) In Supreme Court
 - (B) In High Court
 - (C) In District Court
 - (D) In Both Supreme Court and High Court
- 23. Choose the best option-'Reasoned Decision' means-
 - (A) A Party to a dispute has a right not only to know the decision of a case but also the reason of the decision
 - (B) Right to know decision of the case
 - (C) Right to know reason of the decision
 - (D) Compliance to principle of Natural justice

- 20. निम्न में कौन सी रिट उपचारात्मक प्रकृति की होती है—
 - (A) परमादेश
 - (B) अधिकारपृच्छा
 - (C) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
 - (D) उत्प्रेषण
- 21. उच्चतम न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता संविधान के किन अनुच्छेदों में समाहित है—
 - (A) अनुच्छेद 32 और 217 में
 - (B) अनुच्छेद 32 और 266 में
 - (C) अनुच्छेद 32 और 226 में
 - (D) अनुच्छेद 136 और 226 में
- 22. एक रिट याचिका निम्न में से किन न्यायालयों में दाखिल की जा सकती है—
 - (A) उच्चतम न्यायालय में
 - (B) उच्च न्यायालय में
 - (C) जिला न्यायालय में
 - (D) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में
- 23. <u>सर्वोत्कृष्ट विकल्प</u> को चुने— "सकारण निर्णय" का अर्थ है —
 - (A) विवाद के पक्षकार को वाद का निर्णय जानने के अधिकार के साथ निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार
 - (B) वाद का निर्णय जानने का अधिकार
 - (C) निर्णय के कारण को जानने का अधिकार
 - (D) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का अनुपालन करना

- 24. When personal hearing is given by one officer and order is passed by another officer the principle of natural justice violated is-
 - (A) Right to hearing
 - (B) rule against bias
 - (C) Reasoned decision
 - (D) Both (B) and (C) are ture
- 25. Principles of Natural Justice do not supplant the law of the land but supplement it" This was held in the case of-
 - (A) Menaka Gandhi Vs Union of India
 - (B) A.K. Kraipak Vs Union of India
 - (C) State of U.P. Vs Mohd Nooh
 - (D) A.K. Gopalan Vs state of Madras
- 26. Principle of natural justice are not applicable against which of the following actions-
 - (A) rule making actions
 - (B) Quasi judicial actions
 - (C) Judicial process
 - (D) Administrative actions
- 27. 'Audialteram partem' means-
 - (A) Listening to the appeal
 - (B) Right of fair hearing
 - (C) Right to know reasons of decision
 - (D) Decency in prounouncing a judgement

- 24. जब व्यक्ति सुनवाई का अवसर एक अधिकारी द्वारा दिया जाता और आदेश दूसरे अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तब नैसर्गिक न्याय के किस नियम का उल्लंघन होता है—
 - (A) सुनवाई के अवसर का
 - (B) पक्षपात के विरूद्ध नियम का
 - (C) कारण युक्त निर्णय का
 - (D) (B) और (C) दोनों सही है
- 25. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त किसी विधि को प्रतिस्थापित न कर उसे परिपूर्ण करते है। यह कहा गया था जिस वाद में वह है—
 - (A) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ
 - (B) ऐ०के० क्रेपाक बनाम भारत संघ
 - (C) उ०प्र० राज्य बनाम मोहम्मद नूह
 - (D) ऐ०के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य
- 26. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त निम्न में से किन कार्यवाहियो पर लागू नहीं होंगे—
 - (A) नियम निर्माण की कार्यवाही पर
 - (B) अर्धन्यायिक कार्यवाहियो पर
 - (C) न्यायिक प्रक्रिया पर
 - (D) प्रशासनिक कार्यो पर
- 27. 'ऑडी ऑलटरम पार्टम" का अर्थ है-
 - (A) अपील को सुनना
 - (B) उचित सुनवाई का अवसर
 - (C) निर्णय के आधारों को जानने का अधिकार
 - (D) निर्णय देते हुए शालीनता बनाए रखना

- 28. Dr Bonham's case is related to-
 - (A) Pecuniary bias
 - (B) Personal bias
 - (C) Departmental Bias
 - (D) Subject matter Bias
- 29. Rule of Bias is operative against-
 - (A) Pecuniary Bias
 - (B) Personal Bias
 - (C) Departmental Bias or Bias as to subject matter
 - (D) On All the above
- 30. "No body can be a judge in his own cause" means and refers to-
 - (A) Rule against bias
 - (B) Right of hearing before adjudication
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) Neither (A) nor (B) is correct
- 31. The concept of Natural justice cannot be defined in enactitude yet it imports within its substance certain elements that appeal to the inner conscience of Human by as a whole. The elements included are-
 - (A) Moral considerations of highest form
 - (B) Sense of Justice while taking action
 - (C) Fairness in dead and action
 - (D) All the above

- 28. "डा० बोनहम" का वाद संबंधित था-
 - (A) आर्थिक पक्षपात से
 - (B) व्यक्तिगत पक्षपात से
 - (C) विभागीय पक्षपात से
 - (D) विषय-वस्तु संबंधी पक्षपात से
- 29. 'पक्षपात के विरुद्ध' नियम लागू होता है-
 - (A) आर्थिक पक्षपात के विरूद्ध
 - (B) व्यक्तिगत पक्षपात के विरूद्ध
 - (C) विभागीय पक्षपात अथवा विषयवस्तु संबंध पक्षपात के विरूद्ध
 - (D) उपरोक्त सभी पर
- 30. "कोई भी व्यक्ति स्वयं के वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।" कथन का अर्थ एवं आशय है—
 - (A) पक्षपात के विरूद्ध नियम से
 - (B) निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के अधिकार से
 - (C) (A) और (B) दोनों सही है
 - (D) न तो (A) और न ही (B) सही है
- 31. नैसर्गिक न्याय को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता परन्तु वह अपने सार में ऐसे तत्वों को समावेशित करता है जो कि संपूर्ण मानवता की अन्तर्चेतना को छूती है। समावेशित तत्व है—
 - (A) उच्चतम स्तर के नैतिक मानक
 - (B) कार्यवाही करते वक्त न्यायप्रियता की भावना
 - (C) कार्य एवं स्वाभाव में निष्पक्षता
 - (D) उपरोक्त सभी

- 32. Which among the following is other name of natural justice?
 - (A) Substantial Justice
 - (B) Fundamental Justice
 - (C) Fair play in administrative action
 - (D) All the above
- 33. If the provisions of Article 299(1) are complied with then the contract shall be-
 - (A) Valid and binding upon the Government
 - (B) Such contract can be enforced in state interest and Government can also be sued
 - (C) Both (A) and (B) are correct
 - (D) In case of non compliance of Provisions Government can by ratification adopt the contract.
- 34. The provision of Act 299 (1) are-
 - (A) Mandatory and not directory in nature
 - (B) They are not more formalities but they protect the Governments against unlawful contractors
 - (C) Article 299 (1) prescribes the mode or manner of entering and executing Governmental Contracts
 - (D) All the above are correct

- 32. निम्न में कौन नैसर्गिक न्याय का वैकल्पिक नाम है?
 - (A) सारवान न्याय
 - (B) मूलभूत न्याय
 - (C) प्रशासनिक कार्यो में स्वच्छ (निष्पक्ष) प्रकटीकरण
 - (D) उपरोक्त सभी
- 33. यदि अनुच्छेद 299(1) के प्रावधानों का अनुपालन हो गया हो तो कारित संविदा—
 - (A) वैध होगी तथा सरकार पर बाध्यकारी होगी
 - (B) ऐसी संविदा राज्यहित मे प्रवर्तित की जा सकेगी तथा सरकार के विरूद्ध भी वाद संस्थित हो सकेगा
 - (C) (A) और (B) दोनों सही है।
 - (D) प्रावधानों का अनुपालन न होने पर सरकार अनुसमर्थन कर संविदा को मान्यता दे सकती है
- 34. अनुच्छेद २९९ (1) के प्रावधान है-
 - (A) आज्ञात्मक न कि निर्देशात्मक
 - (B) ये मात्र औपचारिकता नहीं है तथा इनका उद्देश्य अवैध ठेकेदारों से राज्य को सुरक्षा प्रदान करना होता है
 - (C) अनुच्छेद 299 (1) वस्तुतः सरकारी संविदाओं को कारित तथा क्रियान्वित करने के तरीके को बताता है
 - (D) उपरोक्त सभी सही है

- 35. The contractual liability of the central Government and the state Governments is recognized by the constitution under-
 - (A) Article 294
 - (B) Article 298
 - (C) Article 299
 - (D) Under all the above Articles 294, 298 and 299
- 36. Choose best option-

Now for constitutional Torts (Violation of fundamental Rights) Committed by Public servants against citizens in course of duty the supreme court in many cases has held-

- (A) State vicarious liable and awarded compensation to victims
- (B) State not vicarious liable
- (C) No compensation for sovereign Acts is payable
- (D) Sovereign Immunity doctrine has still relevance
- 37. The social welfare nature of state Report of law Commission and post-Kasturilal cases decided by Supreme Court point that-
 - (A) Distinction between sovereign and non sovereign functions should be done away with
 - (B) Encluding enception case of defence, foreign relation etc state should be held liable for tort of its sewas
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) (A) is true but (B) is false

- 35. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का संविदात्मक दायित्व को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है—
 - (A) अनुच्छेद 294 में
 - (B) अनुच्छेद 298 में
 - (C) अनुच्छेद 299 में
 - (D) उपरोक्त सभी अनुच्छेदों 294, 298 तथा 299 में
- 36. सर्वोत्कृष्ट विकल्प चुनें—
 अब यदि राज्य कर्मचारियों द्वारा सेवा के
 दौरान नागरिकों के विरूद्ध संवैधानिक अपकृ
 त्य कारित किये जाते है (मूल अधिकारोका
 हनन) तो उच्चतम न्यायालय ने अपने कई
 निर्णयों में निर्णीत किया है कि—
 - (A) राज्य प्रतिनिहित दायित्व के अधीन दायी होगा तथा पीड़ितों को प्रतिकर भी देगा
 - (B) राज्य प्रतिनिहित दायित्व से दायी नहीं है
 - (C) संप्रभु कार्यों के लिए कोई भी प्रतिकर नहीं देय होगा
 - (D) संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त अभी भी समीचीन है
- 37. राज्य की समाज कल्याणकारी प्रकृति, लॉ कमीशन रिपोंट तथा कस्तूरीलाल वाद के पश्चातवर्ती निणींत वादों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इंगित करते है कि—
 - (A) संप्रभु तथा गैर—संप्रभु कार्यो का वर्गीकरण समाप्त हो
 - (B) रक्षा, विदेशी संबंध इत्यादि अपवादों को छोड़कर राज्य अपने सेवको के अपकृत्यों के दायी हो
 - (C) दोनों (A) और (B) सही है
 - (D) (A) सही है और (B) गलत है

- 38. The cases decided by supreme Court Prior and post kasturilal judgement were by smaller benches and there for technically still today the kasturilal case judgements-
 - (A) Valid and law on the point
 - (B) Doctrine of sovereign immunity still holds ground
 - (C) Later Progressive Judgements are not binding precedent
 - (D) All the above are correct
- 39. In Kasturilal Vs State of U.P. the decision in the Vidhyawati's case was-
 - (A) Affirmed
 - (B) Reversed
 - (C) Sovereign and non sovereign functions doctrine and consequent sovereign immunity doctrine was restored
 - (D) Both (B) and (C) are correct
- 40. In <u>State of Rajasthan Vs</u>
 <u>Vidhyawati</u>. The Supreme Court of India held-
 - (A) State vicariously liable for the tortious (rash and negligent acts) acts of its servants
 - (B) Doctrine of absolute sovereign immunity has no place in social welf are state
 - (C) Public interests demonds state to be liable vicariously to for torts of servents
 - (D) All the above are true

- 38. उच्चतम न्यायालय द्वारा कस्तूरीलाल वाद के निर्णय के पूर्व तथा पश्चात वादों का निर्णय अपेक्षाकृत छोटी पीठ द्वारा किया गया अतः तकनीकी रूप से कस्तूरी लाल वाद का निर्णय है अभी भी—
 - (A) विधिमान्य और विषय पर विधि
 - (B) संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त अभी भी विराजमान है
 - (C) पश्चातवर्ती निर्णीत वाद के निर्णय बाध्यकारी पूर्व निर्णय नहीं है
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
- 39. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में विद्यावती वाद के निर्णय को—
 - (A) संपुष्ट किया गया
 - (B) पलट दिया गया
 - (C) संप्रभु और गैर संप्रभु कार्यो के वर्गीकरण सिद्धान्त को अपनाया गया तथा संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त को पुनः स्थापित किया गया
 - (D) (B) और (C) दोनों सही है
- 40. राजस्थान राज्य <u>बनाम</u> विद्यावती के वाद में उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया—
 - (A) राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों (असावधानी एवं लापरवाह कृत्यों) के प्रतिनिहित दायित्व के अन्तर्गत दायी होगा
 - (B) आत्यांतिक संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त का एक समाज–कल्याणकारी राज्य में कोई स्थान नहीं है
 - (C) लोक हित के दृष्टिगत भी राज्य को अपने सेवको के अपकृत्य के लिए दायी होना चाहिए
 - (D) उपरोक्त सभी सत्य है

- 41. In the famous <u>P&O steam</u> navigation company Vs secretary of state case-
 - (A) Distinction was made between sovereign and non sovereign functions of the government
 - (B) For sovereign functions the state had absolute immunity
 - (C) For non soverign state was made liable as a private citizen
 - (D) All the above are correct
- 42. The tortious liability of central or state governments for the torts committed by its servants is mentioned in-
 - (A) Article 300 (1) of the constitution
 - (B) Article 299 of the constitution
 - (C) Article 278 of the constitution
 - (D) Article 21 of the constitution
- 43. By passing of Crown ProceedingAct. of 1947 in Britain-
 - (A) Sovereign immunity of king for wrongful acts ended and liability established
 - (B) The king can do no wrong maxim was blown away
 - (C) State was now liable for wrongful torts of its servants
 - (D) All the above are true

- 41. प्रसिद्ध पी० एण्ड ओ० स्टीम नेवीगेशन कम्पनी बनाम सचिव, भारत राज्य के वाद में—
 - (A) सरकार के संप्रभु तथा गैर संप्रभु कार्यों में अन्तर किया गया
 - (B) संप्रभु कार्यो के लिए राज्य को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है
 - (C) गैर संप्रभु कार्यो के लिए राज्य प्राईवेट नागरिक के समान दायी है
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
- 42. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों का अपकृत्य दायित्व जो उसके सेवकों के दोषपूर्ण अपकृत्यों के लिए संविधान के जिस अनुच्छेद में वर्णित है, वह है—
 - (A) अनुच्छेद 300(1) संविधान का
 - (B) अनुच्छेद २९९ संविधान का
 - (C) अनुच्छेद 278 संविधान का
 - (D) संविधान का अनुच्छेद 21
- 43. ब्रिटेन में क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के पारित होने से—
 - (A) राजा की दोषपूर्ण कार्यो के संबंध में संप्रभुता उन्मुक्ति समाप्त हो गयी
 - (B) "राज्य कोई गलती कर ही नहीं सकता" सूक्ति विलुप्त हो गयी
 - (C) राज्य अब अपने सेवको के दोषपूर्ण अपकृत्यों के लिए दायी होगा
 - (D) उपरोक्त सभी सही है

- 44. The modern concept of vicarious liability is based on-
 - (A) Social convenience
 - (B) General principle of justice
 - (C) Both on social convenience and gereral principle of justice
 - (D) Respondent superior
- 45. The principle of vicarious liability is traditionally based on the maxim-
 - (A) One who acts through other acts himself
 - (B) Respondent superior
 - (C) An act of an agent-binds the principal
 - (D) All the above
- 46. Government liability in torts committed by its servants be is based fundamentally on the principle of-
 - (A) Vicarious liability
 - (B) Strict liability
 - (C) Absolute liability
 - (D) All of the above
- 47. Non publication and non consultation with interested persons make the delegated legislation-
 - (A) Procedurally ultra vires
 - (B) Substantially ultra vires
 - (C) Both substantially and procedurally ultra vires
 - (D) None of the above

- 44. प्रतिनिहित दायित्व की आधुनिक संकल्पना आधारित है—
 - (A) सामाजिक सुविधा पर
 - (B) न्याय के सामान्य सिद्धान्त पर
 - (C) दोनों सामाजिक सुविधा पर तथा न्याय के सामान्य सिद्धान्त पर
 - (D) प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा पर
- 45. प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धान्त किस परंपरागत सूक्ति पर आधारित है—
 - (A) जो कोई किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कर्ता है कार्य का
 - (B) प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा
 - (C) अभिकर्त्ता का कार्य मालिक को आबद्ध करता है
 - (D) उपरोक्त सभी
- 46. सरकार का दायित्व उसके सेवको द्वारा किए गये अपकृत्यों के लिए मूलतः आधारित है—
 - (A) प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धान्त पर
 - (B) कठोर दायित्व सिद्धान्त पर
 - (C) आत्यान्तिक दायित्व सिद्धान्त पर
 - (D) उपरोक्त सभी पर
- 47. बिना प्रकाशन तथा हितयुक्त व्यक्तियों के परामर्श के अभाव में प्रत्यायोजित विधायन होगा—
 - (A) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (B) मूल अधिकारातीत
 - (C) मूल तथा प्रक्रियात्मक अधिकारातीत दोनों
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 48. The delegated legislation when published takes effect-
 - (A) From the date of publication
 - (B) From date fined in the delegated legislation it self
 - (C) From post publication date
 - (D) From the date prescribed by parent Act
- 49. The rules made in violation of mandatory provitions of the parent Act are-
 - (A) Void and invalid
 - (B) Voidable and invalid
 - (C) Voidable subject to ratification by parent Act
 - (D) Partially void and partially invalid
- 50. When a delegated legislation fails to comply with certain procedural requirements prescribed by the parent Act then such delegated legislation is-
 - (A) Substantially ultra vires
 - (B) Procedurally ultra vires
 - (C) Substantially procedurally ultra vires
 - (D) None of the above
- 51. If the parent Act itself delegates legislative power to the delegate unconstitutionally who according makes the rules and regulations for its implementation. If the parent authority later ratifies such rules and regulation then they be come-
 - (A) Valid
 - (B) Still remain invalid
 - (C) Ratification of unconstitutional authority by parent Act is in itself ultra vires and void
 - (D) Both (B) and (C) are true

- 48. प्रत्यायोजित विधायन जिसका प्रकाशन हो जाता है प्रभावी होगा—
 - (A) प्रकाशन की तिथि से
 - (B) प्रत्यायोजित विधायन में निर्धारित तिथि से
 - (C) प्रकाशन के बाद की तिथि से
 - (D) उस तिथि से जो मूल अधिनियम में निर्धारित की गयी हो
- 49. मूल अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर बनाये गये नियम होंगे—
 - (A) शून्य तथा अविधिमान्य
 - (B) शून्यकरणीय तथा अविधिमान्य
 - (C) शून्यकरणीय तथा मूल अधिनियम के अनुसमर्थन के आधीन
 - (D) अंशतः शून्य तथा अंशतः अविधिमान्य
- 50. जब कोई प्रत्यायोजित विधायन मूल अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं करता तो बना हुआ प्रत्यायोजित विधायन होगा—
 - (A) मूलतः अधिकारातीत
 - (B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (C) मूलतः प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 51. यदि मूल अधिनियम स्वंय असंवैधानिक रूप से विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन करता है, जिसके अनुसरण में डेलीगेट नियम और विनियमन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बना देता है बाद में यदि मूल प्राधिकारी ऐसे नियम और विनियमन का अनुसमर्थन कर देता है तब वे होंगे—
 - (A) विधिमान्य
 - (B) अभी भी अविधिमान्य
 - (C) असंवैधानिक प्राधिकार्णता को मूल अधिनियम द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने पर वह अधिकारातीत और शून्य होगा
 - (D) (B) और (C) दोनों सही है

- 52. In Lohia Machines Vs Union of India AIR 1985 SC. case the supreme court ubserved, "If a rule made by a rule making authority is out side the scope of its power then the rule made by it is-
 - (A) Null and void
 - (B) Voidable
 - (C) Depending upon situation either void or voidable
 - (D) Subject ot ratification by parent Authority
- 53. Exclution of judicial Review from delegative legislation makes it -
 - (A) Invalid being substantively ultra vires
 - (B) Valid
 - (C) Partially invalid
 - (D) Partially valid
- 54. Choose the best option—

A delegated legislation made in compliance of un constitutional point Act is-

- (A) Valid
- (B) Invalid
- (C) Invalid being substantively ultra vires
- (D) None of the above
- 55. Judicial control over delegated legislative can be exercised by the test of -
 - (A) Substantive ultra vires
 - (B) Procedural ultra vires
 - (C) Both substantive and procedural ultra vires
 - (D) Exigency of legislatives and its implementation

- 52. लोहिया मशीनन्स बनाम भारत संघ AIR 1985 SC. में उच्चतम न्यायालय ने यह कथन दिया, "यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अपनी प्राधिकारिता से परे जाकर नियम बनाया हो तो ऐसा नियम होगा—
 - (A) निरर्थक एवं शून्य
 - (B) शून्यकरणीय
 - (C) परिस्थिति अनुसार शून्य या शून्यकरणीय
 - (D) मूल प्राधिकारी के अनुसमर्थन के अधीन
- 53. प्रत्यायोजित विधायन को न्यायिक पुनर्विलोकन से अपवर्जित किये जाने पर वह होगा—
 - (A) अविधिमान्य, मूल अधिकारातीत होने के कारण
 - (B) विधिमान्य
 - (C) आंशिक अविधिमान्य
 - (D) आंशिक विधिमान्य
- 54. सर्वोत्कृष्ट विकल्प चुनें— एक प्रत्यायोजित विधायन जो कि असंवैधानिक मूल अधिनियम के अनुपालन में बनाया गया हो, होगा—
 - (A) विधिमान्य
 - (B) अविधिमान्य
 - (C) अविधिमान्य क्योंकि मूलतः अधिकारातीत होने के कारण
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 55. प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियन्त्रण स्थापित किया है जिस कसौटी द्वारा, वह है—
 - (A) मूल अधिकारातीत कसौटी
 - (B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत कसौटी
 - (C) दोनों मूल तथा अधिकारातीत कसौटी
 - (D) अधिनियम की अपरिहार्यतः एवं क्रियान्वयन कसौटी

- 56. Choose the <u>incorrect option</u>The essential legislative functions are-
 - (A) Repeal of law
 - (B) Removal of difficulties
 - (C) Retrospective operation of an Act
 - (D) Framing of rules
- 57. Henry VIII clause in name of removal of difficulties in implementation of a legislation givesso much power to the executive that it can fiddle with essential legislative powers and hence it is indicative of executive autocracy. The state refers to view of -
 - (A) Lord Hewart
 - (B) Lord Acton
 - (C) Ivor jennings
 - (D) Lord Halsbury
- 58. Henry VIII clause is a-
 - (A) Removal of difficulties clause in a legislation
 - (B) Very wide and authorizes the executive in name of removal of difficulties to modify even the parent act or any other act
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) Promoter of democracy in administration

- 56. निम्न में से गलत विकल्प चुनें— आवश्यक विधायी कार्य है —
 - (A) विधि का निरसन
 - (B) बाधाओं को हटाना
 - (C) किसी अधिनियम का पूर्ववर्ती तिथि से लागू होना
 - (D) नियमो को बनाना
- 57. हेनरी अष्टम खण्ड कार्यपालिका को विधायन को लागू करने में आई बाधाओं को हटानें के नाम पर इतनी असीमित शक्ति देता है किवह आवश्यक विधायी शक्ति, शक्तियों को दुरूपयोग करने लगा जो कि कार्यपालिका तानाशाही का द्योतक है। यह मत है —
 - (A) लार्ड हीवर्ट का
 - (B) लार्ड ऐक्टन का
 - (C) आइवर जेनिन्गस का
 - (D) लार्ड हेल्सबरी का
- 58. हेनरी अष्टम खण्ड है-
 - (A) विधायन की बाधाओं को हटाने वाला खंड
 - (B) बहुत विस्तृत होता है तथा कार्यपालिका को विधायन की बाधाओं को हटाने के नाम पर मूल विधायन या अन्य किसी विधायन को परिवर्तन करने की शक्ति पदान करता है
 - (C) (A) और (B) दोनों सही है
 - (D) प्रशासन में लोकतन्त्र को बढ़ाने वाला है

- 59. Which of the following is not a control on delegated legislation-
 - (A) Doctrine of Ultra vires
 - (B) Judicial control
 - (C) Legislative control
 - (D) Doctrine of lifting of Veil
- 60. Which of the functions cannot be delegated by the legislature?
 - (A) Commencement of the act
 - (B) Inclusion and exclusion clause
 - (C) Application of the existing laws
 - (D) Essential legislative functions
- 61. The function of the Executive can be classified as-
 - (A) Discretionary functions
 - (B) Quasi-judicial functions
 - (C) Delegated legislative functions
 - (D) In All of the above
- 62. As per in Re Delhi laws act case the legislature can-
 - (A) Delegate its essential legislative powers
 - (B) Cannot delegate its essential legislative power
 - (C) Only ancillary legislative power can be delegated
 - (D) Both (B) and (C) are correct

- 59. निम्न में से कौन प्रत्यायोजित विधायन पर नियन्त्रण नहीं है—
 - (A) अधिकारातीत का सिद्धान्त
 - (B) न्यायिक नियन्त्रण
 - (C) विधायी नियन्त्रण
 - (D) घूँघट उठाने का सिद्धान्त
- 60. विधायिका द्वारा कौन से कार्य को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है?
 - (A) अधिनियम की प्रारम्भिक तिथि
 - (B) सम्मिलन तथा अपवर्जन खंड
 - (C) वर्तमान विधियों का लागू रहना
 - (D) आवश्यक विधायी कार्य
- 61. कार्यपालिका के कार्यो का वर्गीकृत किया जा सकता है—
 - (A) स्वविवेकीय कार्यो में
 - (B) अर्द्ध-न्यायिक कार्यो में
 - (C) प्रत्यायोजित विधायी कार्यो में
 - (D) उपरोक्त सभी में
- 62. इन री देहली लॉज एक्ट वाद के अनुसार, विधायिका अपनी—
 - (A) आवश्यक विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है
 - (B) अपनी आवश्यक विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है
 - (C) केवल आनुषंगिक विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन हो सकता है
 - (D) दोनों (B)और (C)सही है

- 63. Point out correct option in Re
 Delhi Laws Act, 1912 case the
 Supreme Court of India held that-
 - (A) Legislative powers can be delegated keeping in view the exigencies moderntimes
 - (B) A Delegate does not stand on the same footing as parliament
 - (C) Delegation of legislative power with restriction is permissible
 - (D) All the above are correct
- 64. The first pre-constitutional case of delegated legislation was that of -
 - (A) Queen Vs Burah
 - (B) Jatindra Nath Gupta Vs Province of Bihar
 - (C) Panama Refining Co. Vs Ryan
 - (D) None of the above
- 65. The factor which is not responsible for growth of delegated legislation is-
 - (A) Technical nature of modern legislation
 - (B) Multifarious increase in the functions of the state
 - (C) Non-participation of elected representatives in debates and absenteeism for political reasons in legislature
 - (D) None of the above

- 63. सही विकल्प का चयन करें— री देहली लॉज एक्ट,1912 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया—
 - (A) वर्तमान समय की अपरिहार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है
 - (B) एक डेलीगेट की स्थिति संसद के समतुल्य नहीं है
 - (C) विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन निर्बन्धों के साथ हो सकता है
 - (D) उपरोक्त में से सभी सही है
- 64. संविधान पूर्व प्रथम वाद जो प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित था, वह है
 - (A) क्वीन बनाम बुराह
 - (B) जतीन्द्र नाथ गुप्ता बनाम बिहार प्रान्त
 - (C) पनामा रिफाइनिंग कंo बनाम रेयान
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 65. वह कारक जो प्रशासनिक विधि के विकास के लिए सहयोगी (उत्तरदायी) नहीं है, वह है—
 - (A) आधुनिक विधायन का तकनीकी होना
 - (B) राज्य के कार्यों में बहुतायात में अभिवृद्धि
 - (C) चुने गये प्रतिनिधियों का परिचर्चाओं में सम्मिलित न होना तथा विधायका में राजनैतिक कारण से अनुपस्थित रहना
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 66. The reason for the growth of delegation legislation is-
 - (A) End of the traditional principle of laissez-faire
 - (B) Establishment of a social welfare state in place of police state
 - (C) Pressure on legislative functions
 - (D) All the above are true
- 67. Point out the <u>incorrect option</u> out of the following"Delegates non potest delegare"
 means
 - (A) A delegate cannot further delegated powers vested in him
 - (B) There is no prohibition for further delegation of powers by the delegate
 - (C) Delegated powers must be exercised by the delegate himself
 - (D) Delegated powers cannot be extended to other authorities by the delegate
- 68. Delegated legislation includes -
 - (A) All rules made by a delegate
 - (B) Regulations and bye-laws made by a delegate
 - (C) Orders or notification issued by the delegate
 - (D) All the above

- 66. प्रशासनिक विधि के विकास का कारण है-
 - (A) यथास्थिति वाद के परंपरागत सिद्धान्त की समाप्ति
 - (B) पुलिस राज्य के स्थान पर समाज-कल्याणकारी राज्य की स्थापना
 - (C) विधायिनी कार्यो पर दबाव
 - (D) उपरोक्त सभी सत्य है
- 67. निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें— "डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे" का अर्थ है—
 - (A) एक प्रतिनिधि अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन नहीं कर सकता
 - (B) प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के पुनर्प्रत्यायोजन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है
 - (C) प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग केवल प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाना चाहिए
 - (D) प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार अन्य प्राधिकारियो पर प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा सकता है
- 68. प्रत्यायोजित विधायन में सिम्मलित है -
 - (A) प्रतिनिधि द्वारा बनाये गये सभी नियम
 - (B) प्रतिनिधि द्वारा बनाए गये सभी रेग्यूलेशन एवं उपनियम (विनियम)
 - (C) प्रतिनिधि द्वारा निर्गत आदेश अथवा अधिसूचना
 - (D) उपरोक्त सभी

- 69. "When the function of legislation is entrusted to organs other than the legislature by the legislature itself then the legislation made by such organs is called-
 - (A) Deemed legislation
 - (B) Delegated legislation
 - (C) Legislation with a difference
 - (D) Parallel legislation
- 70. "The Law making power is vested in the Legislature alone" Delegated legislation is-
 - (A) An exception to above stated rule
 - (B) Is an extension of above rule
 - (C) Part and parcel ofLegislative power
 - (D) Valid always
- 71. the doctrine of "Separation of powers" as propounded by Montesquieu was based on his experiences with-
 - (A) British Legal system
 - (B) American Legal system
 - (C) France's Legal system
 - (D) Both American and French Legal System
- 72. The Article of the Indian constitution which supports 'doctrine of separation of powers' in partial form is-
 - (A) Article 44
 - (B) Article 50
 - (C) Article 51
 - (D) Article 40

- 69. जब विधायन का कार्य स्वयं विधायिका द्वारा विधायिका के अतिरिक्त अन्य अंगों को सुपुर्द किया जाता है तो ऐसे अंग द्वारा निर्मित विधायन कहलाता है—
 - (A) समतुल्य विधायन
 - (B) प्रत्यायोजित विधायन
 - (C) अन्तर के साथ विधायन
 - (D) समान्तर विधायन
- 70. "विधि निर्माण की शक्ति केवल विधायिका में निहित है।" प्रत्यायोजित विधायन है—
 - (A) उपरोक्त वर्णित नियम का अपवाद
 - (B) उपरोक्त वर्णित नियम का विस्तार
 - (C) विधायी शक्ति का अभिन्न भाग है
 - (D) सदैव विधिमान्य
- 71. मोन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित "शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त" जिस विधिक व्यवस्था के अनुभवों पर था, वह थी—
 - (A) ब्रिटिश विधिक व्यवस्था
 - (B) अमेरिकन विधिक व्यवस्था
 - (C) फ्रांस की विधिक व्यवस्था
 - (D) अमेरिकी तथा, फ्रांस की विधिक व्यवस्था पर
- 72. भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' का आंशिक समर्थन करता है वह है—
 - (A) अनुच्छेद 44
 - (B) अनुच्छेद 50
 - (C) अनुच्छेद 51
 - (D) अनुच्छेद 40

- 73. The majority opinion in A.D.M Jablapur Vs Shivakant Shukla case-
 - (A) Supported Rule of law in its true sense
 - (B) Gave a very narrow view of Rule of law
 - (C) Diametrically opposite of minority opinion
 - (D) Both (B) and (C) are true
- 74. The doctrine of separation of powers is applicable in limited form in all legal systems in the sense-
 - (A) Judiciary should always be independently separated from Executive and legislative wing
 - (B) There is an over lapping of legislative and Executive function in all systems of governance
 - (C) Only legislative should be free from influence of both executive and judiciary
 - (D) Only (A) and (B) are true
- 75. Most distinguished writers of administrative law agree that in strict sense doctrine of separation of powers-
 - (A) Is undesirable and impracticable advocates not
 - (B) Advocates that functions of legislature, Executive and Judiciary are independent of each other which is a fallacy
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) Both (A) and (B) are false

- 73. ए०डी०एम० जबलपुर बनाम शिवाकान्त शुक्ला के वाद में बहुमत ने—
 - (A) 'विधि के शासन' का समर्थन उसके वास्तविक स्वरूप में किया
 - (B) 'विधि के शासन' को बहुत संकीर्ण निवर्चन प्रदान किया
 - (C) अल्पमत का ठीक विपरीत था
 - (D) दोनों (B)और (C)सही है
- 74. 'शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त सीमित रूप में सभी विधिक व्यवस्थाओं पर लागू हैं इस अर्थ में कि—
 - (A) न्यायपालिका को सदैव कार्य पालिका तथा विधायिका से स्वतंन्त्र रूप से अलग रखा जायें।
 - (B) सभी शासन प्रणालियों में कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों में आच्छादता रहती है
 - (C) केवल विधायिका को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से स्वतन्त्र रखा जायें
 - (D) केवल (A)और (B)सही है
- 75. प्रशासनिक विधि के सभी प्रतिष्ठित लेखक इस बात पर सहमत है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपने कठोर रूप में—
 - (A) अवाँछनीय और अव्यवहारिक है
 - (B) यह अवधारित करता है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे से स्वतन्त्र है जो कि त्रुटि है
 - (C) दोनों (A) और (B) सही है
 - (D) दोनों (A) और (B) गलत है

- 76. Point out the incorrect option-Doctrine of separation of powers-
 - (A) Advocates decentralization of powers in various organs of the Government
 - (B) Advocates its parallel existence in all legal systems along with rule of law
 - (C) Checks the encroachment of powers of one organ by other through system of check and balance
 - (D) Is not in existence in any Nation in absolute terms
- 77. "Montesquieu looked across foggy England from his sunny Vineyard in Paris and completely misconstrued what he saw". The statement is a -
 - (A) Criticism of Montesquieu Theory of absolute separation of powers among the organs of the government
 - (B) Supports theory of separation of powers
 - (C) Supports the view that in England there existed no system of separation of powers
 - (D) Both (A) and (C) are true
- 78. Doctrine of separation of power means-
 - (A) Each organ of the Government should have only one power
 - (B) One organ of the government should not encroach upon the powers of other
 - (C) One organ of the government should not perform functions of the organ
 - (D) All the above are correct

- 76. गलत विकल्प को चुने— 'शक्ति पृथक्करण' का सिद्धान्त—
 - (A) सरकार के सभी अंगों में शक्ति विकेन्द्रण का समर्थन करता है
 - (B) सभी विधिक व्यवस्याओं में अपना अस्तित्व समान्तर रूप से 'विधि के शासन' के साथ मानता है
 - (C) सरकार के अंग द्वारा दूसरे के कार्यों में अतिक्रमण को 'चेक एवं बैलेन्स' के आधार पर नियन्त्रित करता है
 - (D) किसी भी राष्ट्र में अपने आत्यांतिक रूप में विराजमान नहीं है
- 77. 'मोन्टेस्क्यू ने पेरिस स्थित प्रकाशमान अपने अंगूर के बगीचे से धुंधयुक्त इंग्लैण्ड को देखा और जो देश उसका पूर्णतया गलत आकलन किया।' यह कथन—
 - (A) मान्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के द्वारा शक्तियों के तीनों अंगों में आत्यांतिक वितरण की आलोचना है
 - (B) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का समर्थन करता है
 - (C) इस मत का समर्थन करता है कि इंग्लैण्ड में कभी भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अस्तित्व में था
 - (D) (A) और (C) सही है
- 78. 'शक्ति पृथक्करण' सिद्धान्त से तात्पर्य है कि-
 - (A) सरकार के प्रत्येक के पास केवल एक शक्ति ही होनी चाहिए
 - (B) सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों का अतिक्रमण न करे
 - (C) सरकार का एक दूसरे अंग के कार्यी को न करें
 - (D) उपरोक्त सभी सही है

- 79. French Legal system is known as -
 - (A) Counseil d'etat
 - (B) Droit administratif
 - (C) Judex administratif
 - (D) None of the above
- 80. The principle of "Separation of powers" was for the first systematically and scientifically organized by-
 - (A) Montesque
 - (B) Justice Cordozo
 - (C) Jean Bodin
 - (D) Nietze
- 81. The book 'Spirit of Laws" was written by-
 - (A) Plato
 - (B) Montasque
 - (C) Aristotle
 - (D) Roussaeu
- 82. Point out the incorrect option-Dicey's concept of rule of law in modern times is-
 - (A) Followed by the most democratic countries
 - (B) Both Parliamentary and presidential's systems of Governance recognize it in varying degree
 - (C) Communists Government's also follow rule of law
 - (D) Best antidote for administrative arbitrariness

- 79. फ्रान्स की विधिक व्यवस्था को कहते थे-
 - (A) काउन्सिल डि-इटेट
 - (B) ड्रॉयट एडिमनिसट्रेटिफ
 - (C) ज्यूडेक्स एडिमनिसट्रेटिफ
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 80. 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' को सर्वप्रथम पर व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया था–
 - (A) मोन्टेस्क्यू द्वारा
 - (B) जस्टिस कॉरडोजो द्वारा
 - (C) जीन बोदिन द्वारा
 - (D) नीत्से द्वारा
- 81. "विधियों की भावना" पुस्तक के रचयिता थे-
 - (A) प्लेटो
 - (B) मोन्टेस्क्यू
 - (C) अरस्तू
 - (D) 板 村
- 82. गलत विकल्प को चुने— डायसी के विधि के शासन की संकल्पना वर्तमान में—
 - (A) सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा अनुसरण की जाती है
 - (B) शासन की संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली भिन्न भिन्न मात्रा में इस सिद्धान्त को मान्यता देते है
 - (C) कम्यूनिस्ट सरकारे भी विधि के शासन का अनुसरण करती है
 - (D) प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध यह सबसे बढ़िया प्रतिषेधक दवा है

- 83. Which is the main drawback of Dicey's concept of rule of law?
 - (A) Failure to distinguish between arbitrary power and discretionary power
 - (B) Equating discretionary power with arbitrariness
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) It favored rule by law over rule by men
- 84. Point out the incorrect option-Dicey's concept of Rule of law is-
 - (A) Against wide discretionary powers to administrative authorities
 - (B) Negates rule of men to rule by law
 - (C) Enact equivalent of the concept in equality before law
 - (D) Supportive of supremacy of law
- 85. Dicey's concept of rule of law finds place under the Indian constitution in Article-
 - (A) 21 of the constitution
 - (B) 16 of the constitution
 - (C) 14 of the constitution
 - (D) 15 of the constitution
- 86. 'Recognition of Individual rights under the constitution is not that of much importance unless and until machinery for their enforcementthrough court is present.' This view is attributable to -
 - (A) Locke
 - (B) Dicey
 - (C) Blackstone
 - (D) Edward Coke

- 83. डॉयसी की 'विधि का शासन' को संकल्पना का मुख्य दोष यह है—
 - (A) मनमानी शक्ति तथा स्वविवेकीय शक्ति में अन्तर न कर पाना
 - (B) स्वविवेकीय शक्ति को स्वेच्छाचारिता के समतुल्य मानना
 - (C) (A) और(B) दोनो सही है
 - (D) कि यह विधि को सर्वोच्चता को समर्थित करता है
- 84. गलत विकल्प को चुने— डायसी की विधि के शासन की अवधारणा—
 - (A) प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत स्वविवेकीय शक्तियों को देने के विरूद्ध हैं।
 - (B) व्यक्तियों के शासन को नकारते हुए विधि के द्वारा शासन को बढाती है
 - (C) "विधि के समक्ष समता" संकल्पना की पूर्ण समतुल्य अवधारणा है
 - (D) विधि की सर्वोच्चता को समर्थन करती है
- 85. डायसी की संकल्पना भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में जगह प्राप्त करती है, वह है—
 - (A) संविधान का अनुच्छेद 21
 - (B) संविधान का अनुच्छेद 16
 - (C) संविधान का अनुच्छेद 14
 - (D) संविधान का अनुच्छेद 15
- 86. "किसी संविधान में वैयक्तिक अधिकारों का समावेश मात्र कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान धारण नहीं करता जबतक उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय की मशीनरी उपलब्ध न हो।" यह मत है—
 - (A) लॉक का
 - (B) डॉयसी का
 - (C) ब्लैकस्टोन
 - (D) एडवर्ड कोक का

- 87. Dicey's concept of rule of law supports-
 - (A) Supremacy of the law
 - (B) Equality before law
 - (C) Omnipotence of the spirit of law
 - (D) All the above
- 88. A.V. Dicey's Book which contains the principle of Rule is -
 - (A) Law of the constitutions
 - (B) British law of the constitutions
 - (C) Constitutional process
 - (D) Law and the constitution
- 89. The original propounder of the concept of 'Rule of law was -
 - (A) Jeremy Bentham
 - (B) A.V. Dicey
 - (C) Edward Coke
 - (D) John Stuart Mill
- 90. The whole foundation of administrative law is based fundamentally on the principle of-
 - (A) Rule of law
 - (B) Separation of powers
 - (C) Supremacy of the constitution
 - (D) Public opinion
- 91. In ancient India the main basis of administrative law was-
 - (A) Principle of Dharma
 - (B) Preaching of seers
 - (C) King's command
 - (D) All the above

- 87. डॉयसी की 'विधि के शासन' की संकल्पना समर्थन करती है—
 - (A) विधि की सर्वोच्चता की
 - (B) विधि के समक्ष समता की
 - (C) विधि की भावना की सर्वव्यापकता की
 - (D) उपरोक्त सभी का
- 88. ए० वी० डॉयसी की वह पुस्तक जिसमें 'विधि के शासन' के सिद्धान्त का उल्लेख है वह है—
 - (A) "संविधानों की विधि"
 - (B) संविधान की ब्रिटिश विधि
 - (C) संवैधानिक प्रक्रिया
 - (D) विधि एवं संविधान
- 89. 'विधि के शासन' की अवधारणा के मूल प्रतिपादक थे —
 - (A) जेर्मी बेन्थम
 - (B) ऐ० वी० डायसी
 - (C) एडवर्ड कोक
 - (D) जॉन स्ट्अर्ट मिल
- 90. प्रशासनिक विधि का संपूर्ण आधार मूलतः जिस मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है, वह है—
 - (A) विधि का शासन
 - (B) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त
 - (C) संविधान की सर्वोच्चता
 - (D) लोकमत
- 91. प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का प्रमुख आधार था—
 - (A) धर्म का सिद्धान्त
 - (B) महार्षियों के उपदेश
 - (C) राजा का समादेश
 - (D) उपरोक्त सभी

- 92. The king can do know wrong, long live the king". This statement in English law -
 - (A) Supports administrative law
 - (B) Negates administrative law
 - (C) Partially supports and partially negates administrative law
 - (D) None of the above
- 93. The fundamental principle of administrative law is-
 - (A) Power corrupts and absolute power corrupts absolutely
 - (B) The power vested in administrative authorities should not be unlimited
 - (C) Adequate controls should be placed of powers exercised by administrative authorities
 - (D) All the aboveare true
- 94. Who among the following did not the existence of administrative law in England?
 - (A) A.V. Dicey
 - (B) Maitland
 - (C) Ivor Jennings
 - (D) Blackstone
- 95. The scope of administrative laws intends to-
 - (A) Central and state Tribunals
 - (B) Administrative Decision
 - (C) Quasi-judicial functions of administrative authorities
 - (D) To all the above
- 96. Administrative Law falls in the branch of -
 - (A) Public law
 - (B) Private law
 - (C) Both public and private law
 - (D) In none of the above

- 92. "राजा कोई पाप नहीं कर सकता, राजा चिरायु रहे।" यह कथन आँग्ल विधि में—
 - (A) प्रशासनिक विधि को समर्थित करता है
 - (B) प्रशासनिक विधि को नकारता है
 - (C) आंशिक रूप से समर्थन करता है तथा आंशिक रूप से नकारता है
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 93. प्रशासनिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है-
 - (A) शक्ति भ्रष्ट करती है और आत्यांतिक शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है
 - (B) प्रशासनिक अधिकारियों में निहित शक्तियाँ असीमित नहीं होनी चाहिए
 - (C) प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों पर पर्याप्त नियन्त्रण होने चाहिए
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
- 94. निम्न में से किसने इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि के अस्तित्व को नकारा था?
 - (A) ऐ० वी० डॉयसी ने
 - (B) मेटलैंड ने
 - (C) आइवर जेनिंगस ने
 - (D) ब्लैकस्टोन ने
- 95. प्रशासनिक विधि का क्षेत्र विस्तीर्ण होता है-
 - (A) केन्द्रीय एवं राज्य न्याधिकरणों
 - (B) प्रशासनिक निर्णयों पर
 - (C) प्रशासनिक अधिकारियों के अर्द्धन्यायिक कार्यो पर
 - (D) उपरोक्त सभी पर
- 96. प्रशासनिक विधि, विधि की किस शाखा में आती है—
 - (A) लोक विधि में
 - (B) प्राईवेट विधि में
 - (C) लोक एवं प्राईवेट विधि दोनों में
 - (D) उपरोक्त में से किसी में नहीं

- 97. Administrative Law is the functional side of-
 - (A) Constitutional Law
 - (B) Civil Law
 - (C) Criminal Law
 - (D) Law of Trot
- 98. Who among the following gave this definition of administrative Law?

"Administrative Law is the law relating to administration. It determines to organization, powers and duties of administrative authorities."

- (A) Wade and Philips
- (B) Sir Ivor Jennings
- (C) K.C. Davis
- (D) Prof. M.P. Jain
- 99. Which among the following is not the reason for the growth of administrative law-
 - (A) Technical nature of modern legislation
 - (B) Transformation of state from 'Police state' to 'Social welfare state-
 - (C) Fairness of administration
 - (D) Making emergency provisions for famine and natural calamities
- 100. The reasons for the growth of administrative law is-
 - (A) Social-welfare nature of the state
 - (B) Technological advancement and industrialization
 - (C) Lack of time for parliament to carry its usual functions
 - (D) All the above

97. प्रशासनिक विधि एक क्रियात्मक पक्ष है-

- (A) संवैधानिक विधि का
- (B) सिविल विधि का
- (C) दाण्डिक विधि का
- (D) अपकृत्य विधि का
- 98. निम्न में किसके द्वारा प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा दी गई है?

"प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के गठन शक्तियों तथा कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है।"

- (A) वेड एवं फिलिप्स द्वारा
- (B) सर आइवर जेनिंग्स द्वारा
- (C) के०सी० डेविस द्वारा
- (D) प्रो० एम० पी० जैन द्वारा
- 99. निम्न में से कौन प्रशासनिक विधि के विकास का कारण नहीं है—
 - (A) वर्तमान विधायन का तकनीकी प्रकृति का होना
 - (B) राज्य का संपरिवर्तन 'पुलिस राज्य' से 'समाज–कल्याणकारी राज्य में होना
 - (C) प्रशासन का न्यायसम्यक होना
 - (D) अकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं हेतु आकस्मिक प्रावधान बनाना
- 100. प्रशासनिक विधि के विकास का कारण है-
 - (A) राज्य की समाज—कल्याणकारी प्रकृति का होना
 - (B) तकनीकी अभिवर्धन एवं औद्योगीकरण
 - (C) संसद के पास अपने सामान्य कार्यों को संपादित करने में समय का अभाव
 - (D) उपरोक्त सभी

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

- 1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
- 2. This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.
- 3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
- 4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
- 5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet(O.M.R ANSWER SHEET).
- 6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
- 7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.